भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2299

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2016/7 श्रावण, 1938 (शक) को दिया जाने वाला है)

इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन

2299. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2016 के अंत तक सभी सरकारी लेनदेन के कम से कम 90 प्रतिशत लेनदेन जिसमें नागरिकों और व्यापारियों से भुगतान अथवा प्राप्तियां शामिल हैं, को इलैक्ट्रॉनिक अथवा कागज रहित माध्यम से परिवर्तित करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मार्च, 2016 तक सभी भुगतानों और प्राप्तियों के लिए इलैक्ट्रॉनिक विकल्प प्रदान करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): वर्ष 2015-16 के बजट भाषण (पैरा-64) में की गई घोषणा के अनुपालन में, कार्ड और डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की गई है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में 23 उपाय (19 अल्पावधिक और 4 मध्यावधिक) अनुमोदित किए हैं जिससे निम्नलिखित मदद मिलेगी:

i. प्रत्येक नागरिक को वित्तीय भुगतान सेवाएं प्रदान करने के साथ कार्ड/डिजिटल लेनदेन करने का सामर्थ्य देना।

ii. प्रत्येक भुगतान/संग्रहण डेस्क को कार्ड/डिजिटल प्राप्तियां स्वीकार करने की प्रणाली से लैस करके सरकारी भुगतानों और संग्रहणों को नकद रहित प्रणाली में परिवर्तित करना।

iii. कार्ड/डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन देकर भुगतान लेनदेन को नकद प्रधान से हटाकर नकद रहित व्यवस्था में बदलना।

iv. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए देश में स्वीकृति अवसंरचना का विस्तार करना।

v. कार्ड/डिजिटल भुगतान आसान बनाने के लिए कारपोरेटों, संस्थाओं और व्यापारिक संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

(ग) और (घ): ऐसे भुगतानों को बढ़ावा देने से संबंधित दिशानिर्देश सभी सरकारी विभागों को परिचालित कर दिए गए हैं जो http://finmin.nic.in/the ministry/dept_eco_affairs/currency_coinage/Promo_Payments Means_Card_Digital.pdf वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

******